Volume: 3 Issue: 12 Pages: 32-35

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका: एक विष्लेषणात्मक अध्ययन

[*1] डॉ. भेरूलाल चोरडिया

[*1] (सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र), शासकीय जे.एन.एस.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर, जिला-शाजापुर, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 21/Nov/2024
Accepted: 09/Dec/2024

***Corresponding Author**
डॉ. भेरूलाल चोरडिया
(सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र), शासकीय जे.एन.एस.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर, जिला-शाजापुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश:
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। आधारभूत एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए अपरिहार्य है। कृषि समस्त उद्योगों की जननी, मानव जीवन की पोषक प्रगति का सूचक तथा सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है। किन्तु भारतीय कृषि अपने अविकसित रूप के कारण न तो उसमें कार्यरत व्यक्तियों को उनके श्रम व विनियोजन का उचित प्रतिफल प्रदान करती हैं, ओर न ही वह हमारी खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं की भली भांति पूर्ति कर पाती हैं इसका कारण भारतीय कृषि की अपनी कुछ समस्याएँ है, जिनमें आधुनिक तकनीक का अभाव उत्तम एवं उन्नत बीजों का प्रयोग का अभाव, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, कृषि यंत्रीकरण का अभाव, विद्युत का अभाव, रासायनिक उर्वरकों की कमी आदि ऐसी प्रमुख समस्याएँ है। जो भारतीय कृषि में आज भी विद्यमान है। देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार वर्ष 2015-16 से लगातार कृषि एवं किसान कल्याण एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं। परिणामस्वरूप कोविड़-19 महामारी के दौरान भी कृषि की विकास दर में 3.4 फीसदी की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़ कर 19.9 प्रतिशत हो गई हैं। दिलचस्प बात यह हैं कि इससे पहले 2003-04 में कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20.77 प्रतिशत थी। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सांख्यिकी के अनुसार 2017 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमषः 2.27 प्रतिशत और 1.90 प्रतिशत रहा।

मुख्ये शब्द:- प्रसंस्करण, कृषि वानिकी, कृषि विज्ञान, खरपतवार, पैदावार, कृषि उत्पादन

प्रस्तावना:-

मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भ से ही कृषि लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन रही है। आज भी कृषि विश्व की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय तथा आय का सबसे बडा स्त्रोत है। विकासशील देशों में प्रधान व्यवसाय होने के कारण कृषि राष्ट्रीय आय का सबसे बडा स्त्रोत, रोजगार एवं जीवन-यापन का प्रमुख साधन, औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार है। कृषि इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ तथा विकास की कुंजी है। कृषि विकास के सोपान पर चढ़कर ही विश्व के विकसित राष्ट्र आज आर्थिक विकास के शिखर पर पहुंच सकें है। इंग्लैण्ड, जर्मनी, रूस तथा जापान आदि देशों के विकास में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुदृढ आधार प्रदान किया। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के विचारकों ने कृषि विकास पर पर्याप्त बल दिया है।

आर्थिक विचारों के इतिहास पर यदि ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में कृषि को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता था। भूमि और कृषि प्राचीन आर्य संस्कृति के आधार स्तम्भ है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को माता के पवित्र सम्बंध से सम्बन्धित किया गया है। यहां कृषि कर्म को प्रथम, वाणिज्य को द्वितीय, सेवा कार्य को तृतीय तथा मांगने को चतुर्थ स्थान प्रदान किया गया है। प्राचीन यूनानी विचारकों ने भी कृषि व्यवसाय को विशेष महत्व प्रदान किया था। कोई देश आर्थिक प्रगति के कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों न पहुंच जाए वह कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि कृषि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं - भोजन, कच्चा माल, आवास आदि की पूर्ति करती है। कोई राष्ट्र चाहे कितना ही सम्पन्न हो, वह भोजन कि बिना नहीं रह सकता और न ही ऐसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना उचित कहा जा सकता है।

आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पूंजीवादी तथा समाजवादी समस्त अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को समृद्धिशाली बनाना है। अल्पविकसित तथा विकासशील देश जहां अपनी सामान्य गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और पिछडेपन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते है और अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम विदोहन कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने हेतु प्रयासरत है, वही विकसित देश अपने विकास को निरंतर गतिशील बनाए रखना चाहते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही निरंतर देश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है लेकिन हाल के वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन में देश ने नई ऊंचाईयां हासिल की हैं। देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत कृषि तकनीकियों और किसानों द्वारा इन्हें अपनाने से खाद्यान्न ही नही बल्कि फल-सब्जियों तथा बागानी फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत ने सफलता की नई मिसाल कायम की है। भारत, आज विश्व का शीर्ष फल उत्पादक देश बन चुका है और सब्जी उत्पादन में भी शीर्ष देशों में गिनती होती है। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, नीति क्रांति, पीली क्रांति जैसी अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां भी कृषि विकास की परिचायक हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी की उन्नति में भी कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारतीय संदर्भ में बात करें तो कृषक और ग्रामीण भारत को एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर देखा जा सकता है। इसके पीछे सहज और सरल कारण है देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी की कृषि पर निर्भरता। ग्रामीण जनसंख्या वर्तमान में भी शहरी आबादी की तुलना में कहीं अधिक है। वर्ष 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमान के अनुसार यह संख्या 85 करोड़ से भी अधिक बताई गई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की आजीविका के लिए कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्भरता किसी से छिपी हुई नही है। निकट भविष्य में इस स्थिति में बहुत अधिक बदलाव की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसके विपरित कोरोना काल में शहरों से बडी संख्या में लोगों का गांवो की ओर पलायन होने से यह अनुपात और ज्यादा भी हो सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्न है-

1. ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण विकास की बुनियादी चुनौतियों का अध्ययन करना
3. ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण विकास में उपयोगी वैकल्पिक कृषि व्यवसायों का अध्ययन करना।

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

1. कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि की देश की सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में भागीदारी लगभग 51.9 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2012-13 में घटकर 13.7 प्रतिशत के निम्नतम स्तर तक जा पहुंची थी। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधर पर बात करें तो 17 वर्षो के बाद देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में कृषि की भागीदारी बढ़कर 19.9 प्रतिशत पर जा पहुंची है। इस तथ्य से पुरे देश की अर्थव्यवस्था का कृषि पर निर्भरता का आभास होता है। कोराना संकट की अवधि में अन्य सेक्टर्स की विकास दर काफी नीचे रही थी वहीं दूसरी ओर कृषि विकास दर 3.4 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही । यह देश में कृषि क्षेत्र की क्षमता को इंगित करता है।

2. कृषि और ग्रामीण विकास

मानव विकास के साथ ही कृषि का भी सतत् विकास होता रहा है। तत्कालीन समय में पुरे गाँवो की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि के इर्द-गिर्द ही घुमती थी और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। वस्तुओं की मांग किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित है। यही नहीं, भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है और वहां की सरकारें भी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाऐ बनाती हैं । इस क्रम में कृषि आधारित बुनियादी ढांचे, सब्सिडी आदि पर काफी निवेश भी किया जाता है, ताकि स्थानिय कृषाकों को इसका उत्पादन प्रक्रिया मे लाभ मिले। विकासशील देशों मे संसाधनों के अभाव में सरकारें चाहकर भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती है। ऐसे में किसानों को सामुदायिक आधार पर या व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर संसाधन जुटाने या इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रयास करने पड़ते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि ऐसे प्रयासों के नतीजे अत्यंत उत्साहवर्धक और सकारात्मक होते है। इन संसाधनों का लाभ सामुदायिक स्तर पर स्थानीय लोगों को मिलता है। इतना ही नहीं रोजगार के अवसर, आमदनी में बढ़ोत्तरी और साथ ही जीवन-स्तर में भी बदलाव दिखाई पड़ने लगता है।

3. टिकाऊ एवं समग्र ग्रामीण विकास

बुनियादी तौर पर ग्रामीण इलाके के भीतर होने वाले अवसंरचनात्मक विकास सहित अन्य प्रकार के संसाधनों की निरंतर बढ़ती उपलब्धता को मोटे तौर पर विकास की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरक्ति कृषि प्रगति, वित्तिय एवं सामाजिक ढांचे की स्थापना, रोजगार सृजन, भूमिहीन किसानों के लिए पर्याप्त खाद्य एवं आवास की सुनिशितता आदि भी इसके अहम् हिस्से है। अन्य शब्दों में तो ग्रामीण विकास से आषय है आर्थिक प्रगति, ग्रीमण लोगों की आय में सतत वृद्धि, राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर स्वतंत्रता तथा शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं और संसाधनो तक आसानी से पहुंच।

4. आय बढ़ाने में सहायक

कृषि उत्पादन और इससे जुड़े द्वितीयक उद्योग (प्रसंस्करण, पशुपालन, मछली पालन) ग्रामीण लोगों के लिए न सिर्फ आजीविका अर्जन हेतु प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाते हैं बल्कि रोजगार सृजन के भी महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वैज्ञानिक कृषि के प्रति निरंतर बढ़ती जागरूकता और किसानों द्वारा परम्परागत कृषि के तौर-तरीकों के बदले आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में फसलों की उत्पादकता में अधिक बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। नतीजतन कम निवेश में अधिक लाभ पाने के अवसरों में भी आशातीत वृद्धि किसानों के लिए एक नया अनुभव सिद्ध हो रहा है। प्रयोगधर्मी एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा इस तरह का जोखिम उठाया जाता है और उनकी सफलता को देखकर आसपास के किसान भी सहज ही इस ओर आकर्षित होकर कृषि की तकनीकों को अपनाना शुरू कर देते है। हाल के वर्षो में तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जिनमें किसानों की सफलताओं से प्ररित होकर पुरे गाँव मे परिवर्तन होना है। विश्व बैंक द्वारा भी इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में उच्च दर होने से ग्रामीण निर्धनता को प्रभावी एवं समग्र रूप से दूर करने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है।

5. ग्रामीण विकास में वैज्ञानिक कृषि की भूमिका

कृषि अनुसंधानशालाओं में वैज्ञानिकों की मेहनत से विकसित नई कृषि तकनीकियों, फसल प्रणालियों नई एवं उन्नत किस्मों सहित अन्य जानकारियों को जमीनी-स्तर तक लाने और किसान समुदाय को इनसे परिचित करवाने का दायित्व कृषि प्रसार से जुडे ट्रेंड कर्मियों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये किसानों के बीच रहकर उनको उन्नत तकनीकियों के फायदे और इनके प्रयोग से सम्बंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाते है। कहने की जरूरत नही कि इन सूचनाओं और जानकारियों का

टिकाऊ एवं सतत उत्पादन में बढोत्तरी के रूप में दूरगामी एवं स्थायी प्रभाव किसानों की जिंदगी पर पड़ता है। इस क्रम में मानव श्रम दक्षता में सुधार के रूप में एक अन्य सकारात्मक पहलू भी उभरकर सामने आता है।

ग्रामीण विकास की बुनियादीं चुनौतियां

1. अशिक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर आबादी आज भी कम नहीं है। यही कारण है कि ये समय रहते सही एवं उपयुक्त निर्णय करने में अक्सर असफल रहते हैं और गरीबी के साये से चाह कर भी बाहर निकल नहीं पाते।

2. परंपरागत कृषि से जुड़ाव

जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश ग्रामीण आबादी की आय का मूल स्त्रोत कृषि उन्नति के लोगों की आय में वृद्धि संभव नही है। लकीर के फकीर बने रहने वाले किसानो की दरिद्री का भी संभवतः यही कारण बताया जा सकता है जिसमें कि वे परंपरागत कृषि को त्यागकर वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीकों और फसलक्रमों को अपनाने को आसानी से तैयार नहीं होते है।

3. आधारभूत संरचना और संसाधनों का अभाव

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाओं, विधुत आपूर्ति, ऋण एवं उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार सुविधाओं आदि का अभाव बना हुआ है। सीमित संसाधनों के बूते किए गए सरकारों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं हो सका है। सिंचाई साधनों की कमी और मानसून पर निर्भरता के कारण अधिकांश किसान ज्यादा जोखिम उठाने से डरते है और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से हिचकिचाते है।

4. निम्न कृषि उत्पादन व उत्पादकता

भारत द्वारा निरंतर कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के बावजुद यह कटु सत्य है कि विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में कई महत्वपूर्ण फसलों और कृषि उत्पादों के मामले में देश की औसत उत्पादकता काफी कम है। समय रहते इसमें बढ़ोत्तरी करनी जरूरी है ताकि कम से कम लागत में अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सकें।

5. जलवायु परिवर्तन

वैशिवक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कृषि ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय में कृषि उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के कारण फसल उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी आने की आशंका है। इसी कारण दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल प्रणालियों और तकनीकों के विकास पर जोर दिया जा रहा है ताकि फसलोत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को कम से कम किया जा सके, अन्यथा मानव आबादी के लिए निकट भविष्य में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता हैं।

6. जल की कमी

कृषि क्षेत्र, जल का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता है। बढ़ते जल संकट की वजह से जल का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली फसलों (धान, गन्ना आदि) का अस्तित्व संकट में आ सकता है वैज्ञानिक कम जल के प्रयोग से उत्पादन की नई विधियां और ऐसी ही उपयुक्त किस्मों के विकास पर निरंतर कार्यरत है।

7. भंडारण और परिवहन सुविधाओं का अभाव

अक्सर यह देखने में आता है कि बम्पर फसल उत्पादन की स्थिति में किसानों को मजबुर होकर कम कीमत पर अपनी फसलों (खासतौर पर सब्जियों और फल जैसे तुरंत खराब होने वाले उत्पाद) को बेचना पड़ता है और उनकी लागत तक नहीं निकल पाती। ऐसा शीत भंडारण सुविधा तथा बाजार तक उत्पादों को पहुंचाने संबंधित समुचित परिवहन संसाधनों के अभाव में होता है।

8. स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की कमी

देश में 2011 की जनगणना के अनुसार करीब साढ़े छह लाख गांव है। इनमें छोटे और बड़े हर तरह के गांव शामिल है। इनमें बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा का अभाव है। ऐसे में निर्धनता की स्थिति और संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। इसका परिणाम स्थानीय लोगों के गिरते स्वास्थ्य तथा अशिक्षा के रूप में देखा जा सकता है।

इनके अलावा भी कई अन्य कारण है जिनसे कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी बाधित होती है। इनमें संस्थागत-स्तर पर ऋण सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था, विक्रय हेतु बड़ बाजार का स्थानीय स्तर पर प्रायः अभाव, समय पर कृषि आदानों की अनुपलब्धता, कृषि मशीनीकरण में पिछड़ापन आदि का प्रमुख तौर पर उल्लेख किया जा सकता है।

वर्ष 2022 तक दोगुनी कृषक आय

कृषि विकास से ही ग्रामीण खुषहाली का रास्ता निकलता है। संभवतः इसी सोच के आधार पर वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कृषक आय को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है, ताकि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकें। इस क्रम में लक्षित कार्यो में प्रमुख तौर पर गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढने के कारण कृषि को होने वाली हानि मे कमी एवं कीटों से फसल सुरक्षा जैसे मुद्दो को भी महत्व दिया गया है। कृषि प्रसार कर्मियों द्वारा स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के आधार पर सही एवं उपयुक्त फसल चक्रों की संस्तुति, मृदा जांच के अनुसार खाद ओर उर्वरकों का प्रयोग, समय पर कीटों और रोगो से बचाव आदि जैसे पहलुओं पर समय रहते जानकारियाँ उपलब्ध करवाना आदि इसी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से है।

सरकारी योजनाएं

इसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए ‘‘डिजिटल इंडिया‘‘ कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिसमें इन इलाकों के युवाओं के लिए हुनर आधरित प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित किए जाने का प्रावधान है। यही नही इसमे देशव्यापी स्तर पर समस्त पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था भी है। ‘ई-नाम‘ या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी एक अन्य सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य देशभर के कृषि उत्पादकों को एक विशाल विक्रय मंच प्रदान करते हुए उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलवाना हैं। इनके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे है।

ग्रामीण विकास में कृषि विज्ञान केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान मे कार्यरत देश की शीर्ष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान प्रबंधन संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विज्ञान केद्रों की स्थापना देश के प्रत्येक जिले में कि जा चुकी है। वर्तमान में 722 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। इनके बुनियादी उद्देश्ययों में किसानों, ग्रामीण युवाओं और कृषिरत महिलाओं को वैज्ञानिक खेती से परिचित करवाना, परंपरागत खेती के बदले उन्नत खेती के प्रति जागरूक बनाना, खेत स्तर पर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का आयोजन, स्थानीय जलवायु के अनुसार उन्नत किस्मों और फसलों की संस्तुति करना, अल्प अवधि एवं कम लागत में तैयार होने वाली फसल पद्धतियों के बारे में जानकारी देना,

खाद्य प्रसंस्करण की नई तकनीकों से अवगत करवाना आदि जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल है। साल-दर साल इनके द्वारा आयोजित ट्रेनिंग से लाखों की संख्या में किसान लाभान्वित होते है।

ग्रामीण विकास में उपयोगी वैकल्पिक कृषि व्यवसाय

1. कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण

आलू सहित कसावा, शकरकंद, मिमीकंद टेनिया, याम अरारोट आदि की आधुनिक उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकें अथवा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ आपनाकर किसान अपनी आमदनी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इन केंद्रिय फसलों से कई तरह के मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद भी बनाए जाते है। इनमें प्रमुख तौर पर आलू के चिप्स और कसावा तैयार किए जाने वाले स्नैक्स फूड, पास्ता आदि का जिक्र किया जा सकता है। जैव इथेनोल उत्पादन में भी कसावा का कम महत्व नहीं है। आने वाले समय में इन उत्पादों की पोषण महत्व के कारण मांग बढ़नी स्वाभाविक है। इसी तरह से शहरी जीवन में इंस्टेंट फूड के तौर पर भी इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है।

2. औषधीय पौधों की खेती

इसबगोल के बीज के आवरण को भूसी के नाम से जाना जाता है और इसमें कई तरह के औषधीय गुण होते है। वैशिवक बाजार में इसबगोल की भूसी निर्यात करने वाला भारत एकमात्र देश है। इसकी व्यावसायिक खेती से आकर्षक कमाई बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसी तरह से कलोंजी, करी पत्ता, लैमन घास, अशवगंधा, शतावर, सफेद मूसली, मेथे सहित अन्य औषधीय महत्व के पौधों की व्यावसायिक खेती पर जोर दिया जा सकता है।

3. कोको उत्पादन से आमदनी

देश में दूध और कोको उत्पादन बढ़ने से चॉकलेट उद्योग मे अधिक तेजी देखने को आ रहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ चॉकलेट इंडस्ट्री में ठहराव की स्थिति आ रही है तो वहीं दूसरी और भारत में यह काफी तेजी से तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में देश के दुग्ध एवं कोको उत्पादक कृषक चॉकलेट उद्यमी के तौर पर अपनी आमदनी को अधिक बढ़ा सकते है। सरकारी तौर पर भी इस उद्यम को अपनाने वाले किसानों को सुविधायें प्रदान की जा रही है। इस व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में भी ग्रामीण युवा बड़े पैमाने पर अपनाने के बारे में सोच सकते है।

4. लाख की खेती

लाख करीना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के किट पलाष, कुसुम, तथा बेर के पेडों पर पाले जाते है। इन वृक्षों की शाखाओं से ये कीट रस चुसकर अपना आहार प्राप्त करते है। ये कीट अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर एक प्ररकार का कवच अपने चारों ओर बना लेते है। यही राल बाद में लाख के रूप में टहनियों से खुरचकर निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसे उद्योग का दर्जा दिए जाने से इसके उत्पादकों को बडी आसानी से ऋण सुविधाएं भी अब मिल सकती है।

5. कृषि वानिकी से आय

कृषि वानिकी का महत्व कृषक आय बढ़ाने में कम नहीं है। अब तब कृषि वानिकी को महज इमारती लकड़ी प्राप्ति का एक जरिया माना जाता था। बदलते समय के साथ इस सोच में बदलाव आया है और कृषि वानिकी के माध्यम से अब औषधीय एवं संगधीय पौधों का बड़ पैमाने पर उत्पादन, कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के तौर पर आवश्यक लुगदी, जैव ईधनों के उत्पादन के लिए पेड़ जनित बीजों का उत्पादन, रेशम कीट पालन जैसी अनेक संभावनाएँ सामने आई है।

6. खरपतवार को बनाएं आमदनी का जरिया

कई खरपतवार ऐसी भी होते है जिनका औषधियों के उत्पादन में अधिक महत्व हैं। ऐसे खरपतवारों के उत्पादन से किसान कमाई कर सकते है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संचालित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ऐसे महत्वपूर्ण खरपतवारों के औषधीय गुणों की पहचान करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम विकसित करने में जुटा हुआ है। ऐसे खरपतवारों में चिरचिटा, पुनर्वा, इन्द्रायण, चामकस, शंखपुष्पी, मकोय, सर्फोका, त्रिकंटक आदि का नाम उल्लेखनीय हैं।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्पविकसित देशों की कृषि विकास दर में वांछित सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में उपयुक्त संस्थागत सुधारों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा भूमि व्यवस्था को समाजिक ढांचे के अनुरूप वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए। वास्तव में इन देशों को सन्तुलित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सहित विकास के लिए भूमि व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। विकास की ओर उन्मुख घनी आबादी वाले ये देश, जहां व्यापक बेरोजगारी, अर्ध-बेरोजगारी विद्यामन है, कृषि विकास की अवहेलना नहीं कर सकते । खाद्यानों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा कुल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके विपणन योग्य आधिक्य का सृजन करना इन देशों की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सत्य तो यह है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति किए बिना तीव्र अधिकांश अल्पविकसित देश कृषि विकास की दिशा में सकारात्मक रूख अपनाए हुए हैं तथा देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुरूप कृषिगत विकास हेतु सतत प्रयासरत है।

संदर्भ-सूची:

1. अग्रवाल पी.के. (2010) कृषि अर्थशास्त्र, संजीव प्रकाशन मेरठ।
2. मिश्र जय प्रकाष (2010) कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. दत्त रूद्र एवं सुन्दरम के.पी.एम (2014) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द्र एण्ड लिमिटेड नई दिल्ली।
4. सिंह एस.पी. (2015) आर्थिक विकास एवं नियोजन, एच.चन्द्र एण्ड लिमिटेड नई दिल्ली।
5. प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था (अतिरिक्त संचालक) उपकार प्रकाशन आगरा।
6. योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. कुरूक्षेत्र, सूचना भवन सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स लौधी रोड़ नई दिल्ली।
8. www.mpkrsi.org/engdocs//agrimarket/aspx